

मिति २०८१/११/२६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पठाइएको मुद्दाको विवरण

सि.नं.	प्रतिवादीहरू	मुद्दा	आयोगको मागदावी	विशेष अदालतको फैसला र आधार	आयोगबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरू
	घनश्याम बानिया, याम बहादुर ठकुरी, हरि कुमारी महत, याम बहादुर बानिया, धुन बहादुर पुलामी मगर, खडक बहादुर बानिया, ज्ञान बहादुर बानिया, सन्त बहादुर सिजाली मगर, तिलुदेवी बराल, शरण बहादुर बि.क, विष्णुमाया थापा स्याङजा, लोक बहादुर माक्रिम, डिल बहादुर आले,	सार्वजनिक जग्गा आफै कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको	प्रतिवादीहरू घनश्याम बानिया, यम बहादुर ठकुरी, हरि कुमारी महतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) (ज) बमोजिमको कसुरमा निज प्रतिवादीहरूलाई सोहि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरूको निर्णयले बिक्री भएको जग्गाको कूल रकम रु १,६९,०५१।०० विगो कायम गरी सजाँय हुन मागदावी लिइएको। प्रतिवादीहरू याम बहादुर बानिया, धुन बहादुर पुलामी, ज्ञान बहादुर बानिया र खडक बहादुर बानियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) (ज) बमोजिमको कसुरमा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को	<b>फैसला:</b> प्रतिवादीहरूलाई आरोपदावीबाट सफाई दिने ठहर गरी फैसला भएको। विशेष अदालतले फैसला गर्दा लिएका आधार: <b>क.</b> हिमाली प्रा.वि.तनहुँको व्यवस्थापन समितिको निर्णयले व्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण दा.खा. भई गएको नदेखिएको। <b>ख.</b> स्कूलको नाममा नै नभएको जग्गा बिक्री गर्ने भनी मिति २०५१।०१।११ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय एवं घरसारको लिखत आफैमा	उल्लिखित आधारहरूलाई विशेष अदालत काठमाण्डौबाट प्रतिवादीहरूलाई आरोप मागदावीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला देहायका आधार, कारणहरूबाट सो हदसम्म बदरबागी रहेको छ। <b>क.</b> हिमाली प्रा.वि. तनहुँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५१।१।११ गते भएको बैठकको निर्णयले सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजातहरू बनाई विद्यालय आफैले घडेरी नम्बर कायम गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रतिवादीहरूबाट जम्मा रु.१,६९,०५१।०० लिनु/दिनु गरी प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी रूपमा सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई भोग चलन समेत गरे/गराएको भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँको च न ९३, मिति २०७८।४।५ गते को रायसहितको प्रतिवेदनमा सरकारी पर्ति जग्गा विद्यालयले व्यक्ति सरह बेचबिखन गरी तत् पश्चात पनि घरसारको कागजबाट पुनः बेचबिखन भएको देखिदा उक्त कार्य कानून विपरित भएको कुरामा कुनै विवाद रहेन। बिक्री भएका जग्गा घडेरी मध्ये १० वटामा पक्की घर बनेका एवं अन्य घडेरीमा कच्ची घर तथा संरचना बनेका र केहि जग्गा घडेरी खाली रहेको पाईयो। उक्त कार्य गैरकानूनी देखिएको हुँदा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कानूनी कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ, भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ भने हिमाली प्राथमिक विद्यालय तनहुँको च.नं. ३६, मिति २०७४।३।२७ को रायसहितको प्रतिक्रियामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी २१ जनालाई बिक्री गरी दिएको १४ वटा भरपाई रहेको देखिन्छ। यसरी कानूनमा हुदै नभएको आफूलाई नरहे नभएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषलाई घरसारको लिखत मार्फत परित गरिदिने कार्य गरेको भन्ने तथ्यहरू हिमाली प्रा.वि. विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०५१।१।११ मा गरेको निर्णयको प्रतिलिपिले थप पुष्टि गरेको देखिन्छ। <b>ख.</b> प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले मौकाको बयानमा विद्यालयको जग्गा बिक्री वितरण गरेको कसूरलाई स्वीकार गरी बयान गरेका छन्। मिसिल सामेल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५१।०१।११ को निर्णयको नि.नं. १. मा "कक्षा २ का विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै कोठको अभावमा पठनपाठन कार्यमा बाधा पुगेकोले कक्षा कोठा बनाउनका साथै भौतिक विस्तारका लागि स्थानीय श्रम बाहेक आवश्यक रकम जुटाउनकोलागि घडेरी बेच्ने निर्णय

<p>विष्णु प्रसाद लम्साल, बुद्धीमाया वि.क., बाबुराम बानिया, बलराम भन्ने विनि बहादुर भन्ने विनि बहादुर बानिया, पूर्ण बहादुर वि.क., दोलनाथ आचार्य, धन बहादुर वि.क. (विशेष अदालतको मुद्दा नं. ०७८-CR-००६२ र फैसला मिति २०८०/११/१४)</p>		<p>उपदफा (१) बमोजिम निजहरुसमेतको निर्णयले विक्री भएको जग्गाको कूल रकम रु.१,६९,०५१।०० विगो कायम गरी सजाय हुने भएतापनि निज प्रतिवादीहरुको मृत्यु भईसकेको भन्ने अनुसन्धानबाट खुलेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम विगो रु.१,६९,०५१।०० निज प्रतिवादीहरुबाट असुल हुन मागदावी लिइएको। प्रतिवादीहरु सन्त बहादुर सिजाली मगर, तिलुदेवी वराल, पूर्ण बहादुर वि.क., डिल बहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णु प्रसाद लम्साल, शरण बहादुर वि.क., बलराम भन्ने विनि बहादुर बानिया, बुद्धीमाया वि.क., बाबुराम बानियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १(ज)</p>	<p>कानूनी मान्यता शून्य (Null and void) रहेको देखिएको। ग. सार्वजनिक जग्गामा बनेको अनाधिकृत संरचना मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०७ बमोजिम जुनसुकै वखत सूचना दिई हटाउन सक्ने देखिएको। घ. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५१।०१।११ मा भएको निर्णय तथा सो बमोजिमको घरसारको लिखतका सम्बन्धमा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिमको आरोपदावी नलिएको।</p>	<p>गरिन्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यसै गरी शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको पत्रको बुँदा नं. १ मा “२२ वटा घडेरी करिव ४-११-१-२ क्षेत्रफल भएको र विद्यालयको उत्तर पूर्वको भरपाखोमा करिव २ रोपनी जग्गा तथा घडेरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५१।१।११ को निर्णयबाट विद्यालयको कक्षा कोठा बनाउने प्रयोजनको लागि विक्री गरेको” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यसैगरी विद्यालयको गैरकानूनी निर्णयबाट जग्गा कागज गरी लिने विष्णु प्रसाद लम्सालले “सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले आवाद गर्नुहुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था मलाई थाहा छ। ट्रेस राखी घर बनाएको छु। स्कूलसंग लिएको जग्गा पैसा तिरी सकेको हुँदा कानूनी कारवाहीको दायरामा आउनुनपर्ने हो” भन्ने वयान उल्लेख गरेबाट निज प्रतिवादीहरुले उक्त जग्गा हक भोग गरिरहेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ। जग्गा नामसारी, सेतापुर्जा दा.खा नभएता पनि भोग गर्न दिएको र भोग गरिरहेको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ती गैरकानूनी रूपमा आफ्नो वा अरुको नामा दर्ता भोगचलन गर्ने गराउनेलाई कसूरदार ठहर गर्नु पर्नेमा हिमाली प्रा.वि.तनहुँको व्यवस्थापन समितिको निर्णयले व्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण दा.खा. भई गएको नदेखिएको भन्ने आधार ग्रहण गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा त्रुटीपूर्ण हुँदा बदरभागी छ। ग. प्रस्तुत मुद्दाको विवादित जग्गा तत्कालिन ढोरफिर्दि गाविस र वडा नं ७ को वडा कार्यालयले २०५० सालतिर विद्यालय भन्दा अलि तलतिर करीब ७ रोपनी पर्ति ऐलानी जग्गा विद्यालयले भोगचलन गरी खानु भनी लिखित गरिदिएको तर अभिलेख नभएको र द्वन्दकालमा गाविसमा आगलागि भएकोले नष्ट भएको भन्ने मौखिक जानकारी दिएको भन्ने ब्यहोरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुँका स्रोत व्यक्ति द्वय धन नारायण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र कुमार कर्णले मिति २०७४।६।२७ मा पेश गरेको संयुक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै तत्कालिन ढोरफिर्दि गाविस र वडा नं ७/ठ को कि.नं.५ को फिल्ड बुक उतार कि.नं. ५ बाट किताकाट भई कि.नं. २३ र २४ को प्लट रजिष्टर उतार, कि.नं. २३ बदर भएको देखिन्छ भनी नापीका सेर्भेक्षकहरुले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा नापी कार्यालय तनहुँको मिति २०७४।१२।२६ को पत्रबाट देखिन्छ। विद्यालयसंग घडेरी किन्नेहरुका तिनपुस्ते विवरण फोटोहरु ईत्यादि प्रमाणहरु संलग्न राखिएको मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट सरकारी पर्ति जग्गा विद्यालयले व्यक्ति सरह काल्पनिक घडेरी नम्बर कायम गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति गैर कानूनीरूपमा वेचविखन गरी भोगचलन गर्ने गराउने तत् पश्चात पनि घरसारको कागजबाट पुनः वेचविखन भएको देखिदा उक्त कार्य कानून विपरित भएको</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बमोजिमको कसुरको मतियारका रूपमा कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम ऐनको दफा ८(१) बराबरको सजाय हुन तथा ऐनको दफा ४७ बमोजिम निज प्रतिवादीहरूले भोग गरेको माथि उल्लेखित जग्गा प्रतिवादीहरूबाट भोग हटाई जफत समेत गरी पाउन मागदावी लिइएको। प्रतिवादीहरू लोक बहादुर माकिम, दोलनाथ आचार्य र धन बहादुर वि.क.ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) (ज) बमोजिमको कसुरको मतियार भएको देखिएकोले सोही ऐनको कसुरमा दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय तथा दफा ४७ बमोजिमको

कुरामा कुनै विवाद रहेन। सो तथ्यमा अदालतको फैसला हेर्दा स्वयं अदालत समेतले उक्त सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा हकभोग भएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेकै अवस्था देखिन्छ। अतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गैरकानूनी निर्णयबाट सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा व्यक्ति विशेषले किनवेच, हकभोग तथा पुन किनवेच समेत गरेको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय एवं घरसारको लिखत आफैमा कानूनी मान्यता शून्य हुने भनी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला तथ्यको विप्लेषणमा त्रुटीपूर्ण हुँदा बदरभागी छ।

घ. प्रस्तुत मुद्दा तत्कालिन हिमाली प्राथमिक विद्यालय तनहुँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५१।१।११ गतेको गैरकानूनी निर्णयले "विद्यालयको अवस्था अति नै जिर्ण रहेकोले भवन निर्माणको लागि आवश्यक रकम जुटाउन ..... चारकिल्ला भित्रको सार्वजनिक जग्गा नि.नं. १ अनुसार घडेरी बेच्ने निर्णय भएकोले ..... को जग्गा रु..... यस विद्यालयको खातामा आम्दानी गरी यो भरपाई तपाईं..... लाई माथि उल्लेखित जग्गा तपाईंको हकमा हुनेगरी यस विद्यालयबाट यो भरपाई गरी दियो" भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याम बहादुर वानीया र प्र.अ. याम बहादुर खाणले हस्ताक्षरित भरपाई कागज गरी गैरकानूनी तवरबाट रकम लिई "आगामी आउने नापी सर्वेमा नापजाँच गराई लिनुहोला" भन्ने उल्लेख गरी दिएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी प्रमाणित गरिएको प्रमाण पत्र सहित विद्यालयको घडेरी जग्गा वितरण गरेको तथा निज जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले समेत गैरकानूनी तरीकाले प्राप्त गरेको जग्गाहरूको भोग चलनलाई निरन्तरता दिई रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। यसरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले हिमाली प्रा.वि. तनहुँको भोगाधिकार रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा रकम लेनदेन गरी किनवेच गरी आफ्नो वा अरुको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने गराउने कार्य गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ज) बमोजिमको कसूरमा सजायको मागदावी लिई आरोप पत्र दायर गरिएको हो। त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ मा गरिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा गरिएको विशेष व्यवस्थाले समेत नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुऱ्याएकोमा सो असुल उपर गर्न छुट्टै मुद्दा दायर भएकोमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा छुट्टै मुद्दा चलाउने वाधा पर्ने छैन भन्ने विशेष व्यवस्था समेत रहेकोमा प्रतिवादीहरूलाई कसूरबाट उन्मुक्ति दिने अभिप्रायले सार्वजनिक जग्गामा बनेको

		<p>सजाय हुन मागदावी लिइएता पनि निज प्रतिवादीहरुको मृत्यु भईसकेको भन्ने अनुसन्धानबाट खुलेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम प्रतिवादीहरुले गैर कानूनीरूपमा भोग गरेको सरकारी जग्गा (सम्पत्ति) भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत हुन मागदावी लिइएको</p>		<p>अनाधिकृत संरचना मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०७ बमोजिम जुनसुकै वखत सूचना दिई हटाउन सक्ने देखिएको भन्ने आधार ग्रहण गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसूरबाट प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला कानूनी व्याख्याको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ।</p> <p>प्रस्तुत मुद्दाका स्थलगत प्रतिवेदक स्रोत व्यक्ति धन नारायण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र कुमार कर्णले तयार गरेको हिमाली प्राथमिक विद्याय शुक्लागण्डकी नगरपालिका ९ तनहुँको र स्थलगत अनुगमन गरी विद्यायबाट प्राप्त गरेको सेस्ता अभिलेखहरु बैठक पुस्तिका लगायत भैतिक विस्तारका सम्बन्धमा सोधनी गरी पेश गरेको प्रतिवेदनलाई अदालतको बकपत्र समेतबाट पुष्टि गरेको हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम उक्त बकपत्र प्रमाणमा ग्रहण गर्नु पर्नेमा सो बकपत्रको कुनै मूल्यांकन नगरी भएको प्रस्तुत फैसला बदरभागी देखिन्छ। साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५१।०१।११ मा भएको निर्णयले नै प्रस्तुत मुद्दाको वारदात घटेको देखिन्छ तर सो निर्णयबाट भएको घटनाको निरन्तरता हालको अवस्थामा समेत रहेको देखिन्छ विद्यालयको निर्णयले वितरित जग्गामा हालसम्म पनि गैरकानूनी हकभोग रहेको देखिएकोले कसूरको निरन्तरता देखिन्छ। तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले कसूर मानेको गैरकानूनी हकभोगलाई हालको ऐनले समेत कसूर नै मानी सजायको व्यवस्था गरेको अवस्थामा गैरकानूनी कार्य गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गरी दण्डहिन्तालाई अन्य गर्नु पर्नेमा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिमको आरोपदावी नलिएको भन्ने आधार ग्रहण गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिई कसूरदारलाई प्रश्रय दिएको प्रस्तुत फैसला त्रुटीपूर्ण रहेकोले उक्त फैसला बदर गरी पाउँ।</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------